हरिभूमि

शौर्य भूमि

मंडला | अंजिनया | भुआबिछिया | बम्हनीबंजर | नैनपुर | निवास | बीजाडांडी

जबलपुर, बुधवार 17 जून 2026

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

युवा संगम रोजगार मेले में 51 युवाओं का प्रारंभिक चयन, 8 को अप्रेंटिसशिप का अवसर

मण्डला। जिला प्रशासन मण्डला के निर्देशानुसार जिला रोजगार कार्यालय मण्डला, आईटीआई मण्डला एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मण्डला द्वारा संयुक्त रूप से 16 जून को नगरपालिका मण्डला के सभागार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय एवं निजी क्षेत्र की 6 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान किए। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा रोजगार मेले के महत्व पर प्रकाश डाला। रोजगार मेले में कुल 89 आवेदकों का पंजीयन किया गया। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के बाद 51 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया, जबकि 8 युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा 2 हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में रोजगार संबंधी विभिन्न योजनाओं एवं अवसरों की जानकारी प्रदान की गई। मंच संचालन प्रशिक्षण अधिकारी वैशाली कामड़े द्वारा किया गया। इस अवसर पर आईटीआई प्राचार्य मनीषा भूरिया, जिला रोजगार अधिकारी श्रीमती सुषमा विश्वकर्मा, सहायक संचालक बलराम यादव, सहायक संचालक अन्य पिछड़ा वर्ग दिलीप श्रीवास, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मण्डला के प्रबंधक प्रदीप जायसवाल, आईटीआई प्लेसमेंट ऑफिसर आनंद मरावी, डी.के. साहू सहित जिला रोजगार कार्यालय एवं अन्य विभागों का स्टाफ उपस्थित रहा।

यूसीसी का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को समान अधिकार दिलाना है-बुधपाल सिंह

समान नागरिक संहिता पर हुआ मंथन

*** आमजनों से लिए गए सुझाव।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य शासन द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के तहत मंगलवार 16 जून को पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बड़ी खैरी के सभागार में उच्च स्तरीय समिति की ओर से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूसीसी के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य श्री बुधपाल सिंह ने संहिता के प्रावधानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सुझाव एवं विचार प्राप्त किए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय कुशराम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा, मंडला जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष सोनू भलावी, पूर्व विधायक श्री अशोक मर्सकोले, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती राधा गुप्ता, कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना, संयुक्त कलेक्टर श्री हुनेन्द्र घोरमारे, डिप्टी कलेक्टर श्री संस्कार बावरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए समिति सदस्य श्री बुधपाल सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि गोवा में आजादी के पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है और गोवा के 1961 में भारत में विलय के बाद भी यह व्यवस्था जारी रखी गई। वर्तमान में उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में भी यूसीसी लागू है तथा मध्यप्रदेश इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसे लागू करने वाला चौथा राज्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित व्यवस्था में जनजातीय समुदाय की परंपराओं को देखते हुए, अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

श्री बुधपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान में विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत आते हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि यूसीसी लागू होने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। यह कानून किसी भी धर्म की पूजा-पद्धति या धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यूसीसी लागू होने पर विवाह पंजीयन अनिवार्य होगा, बेटी और बेटे को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, गोद लेने की प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष होगी, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अलग प्रावधान बनाए जाएंगे तथा बहुविवाह पर रोक लगेगी, जिससे महिलाओं को और अधिक सुरक्षा मिलेगी।

बैठक में उपस्थित नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने विवाह एवं विवाह विच्छेद के लिए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए जाने, महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों में समानता सुनिश्चित करने तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जन्में बच्चों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही धर्मांतरित जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए प्रावधानों में व्यवस्था की स्पष्टता पर जोर दिया। वहीं लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर भी स्वतंत्र विचार रखे गए। इसके अलावा विवाह पंजीयन को अनिवार्य बनाने, बेटा-बेटी को समान संपत्ति अधिकार प्रदान करने तथा अनुच्छेद-44 एवं यूसीसी के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के सुझाव भी दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय कुशराम, पूर्व विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती राधा गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मंजु कछवाहा, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष श्री पारस असरानी, वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रेश खरे, सामाजिक कार्यकर्ता श्री विनय मिश्रा, श्री रामकुमार हरदहा, जनाब उस्मान, सब इंजीनियर सुश्री रमा सहित अन्य गणमान्य नागरिकों तथा महिलाओं ने अपने विचार समिति के सामने रखे।

समिति सदस्य श्री बुधपाल सिंह ने बताया कि जो लोग बैठक में अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, वे नबबण्उचण्हवअण्पद पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे विधि विभाग की सहमति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के विचारों को समाहित करते हुए आगे की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

परिक्रमा मार्ग पर स्थित मांसाहार की दुकानों को स्थानांतरित किया जाये

*** आम आदमी पार्टी मंडला ने जनसुनवाई में दिया आवेदन।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

आम आदमी पार्टी मंडला के द्वारा लगातार जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी मंडला के द्वारा नर्मदा भक्तों की महत्वपूर्ण जनहितैषी मांग को लेकर जनसुनवाई में आवेदन दिया गया। आम आदमी पार्टी मंडला के जिला अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि सनातन धर्म में धार्मिक यात्राओं में से एक नर्मदा परिक्रमा हर एक सनातनी और नर्मदा भक्तों के लिए आस्था का विषय है। परंतु नर्मदा परिक्रमा मार्ग के अनेक स्थानों पर मांसाहार की दुकानें संचालित होती है। जिसके कारण यात्रा करने वाले भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे ही कई स्थानों में से एक कारीकोन तिराहे से गैस गोदाम तक के मार्ग में अनेक मांसाहार की दुकानें संचालित होती हैं। जिसके कारण परिक्रमा वासियो को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसी मार्ग पर गैस गोदाम एवं गिट्टी क्रेशर होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। एवं परिक्रमवासियों के साथ वहां के रहवासियों और खरीददारों को भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी मंडला के द्वारा आवेदन देकर इस महत्वपूर्ण विषय पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया है।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि वहां के व्यापारियों के व्यापार में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भीड़ अधिक होने से व्यापारी वहां सामान खरीदने नहीं जाते हैं। अतः दुकानों को ऐसी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। जहां व्यापारियों का भी व्यापार में बढ़ोत्तरी हो सके। और हमारी आस्था भी बनी रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी मंडला के जिला अध्यक्ष पंकज सोनी, जिला संगठन मंत्री शिशु सिंधु भलावी, जिला संगठन मंत्री (एस. सी. विंग) नितिन झरिया, जिला अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ) रमा देवी धुर्वे, जिला मीडिया प्रभारी आशीष वैष्णव, जिला कार्यालय प्रभारी राजेश महोबिया, राकेश उसराठे, रश्मि मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

मण्डला। मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से प्रदेश में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक सभी नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बंद ऋतु के दौरान नदियों, जलाशयों एवं निर्धारित जल स्त्रोतों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मछलियों का विक्रय तथा परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। शासन द्वारा यह कदम मछलियों की प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित रखने तथा मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम, 1981 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास, 5 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। मत्स्य विभाग ने सभी मत्स्य समितियों, मत्स्य समूहों, निजी मत्स्य पालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे 16 जून से 15 अगस्त तक किसी भी प्रकार के अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय-विक्रय में सहयोग न करें तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंध अवधि में उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानांतरण प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

शासन द्वारा घोषित स्थानांतरण नीति के उलट जिले में चीन्ह-चीन्ह कर उन्हें स्थानांतरण का लाभ दिये जाने के आरोप लग रहे हैं जो या तो पैसे वाले हैं या पहुंच वाले हैं। जिले से भेजी गई सूची में बहुतो के नाम अलग कर दिये जाने की खबरें आ रही हैं यह सब क्यों और कैसे हो पा रहा है इसको लेकर तरह-तरह की चर्चायें जोरो पर है। प्रभारी मंत्री की सहमति होना आवश्यक है अब प्रभारी मंत्री कौन बतायेगा कि किसका स्थानांतरण प्रशासनिक हित में है अथवा नहीं। और यही वह पेंच हैं जिसके चलते यह पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मंडला जिला के वन विभाग की स्थानांतरण सूची नोडल अधिकारी एवं वन मंडल अधिकारी पूर्व सामान्य मंडला द्वारा कलेक्टर के हस्ताक्षर उपरांत मंडला जिले की स्थानांतरण सूची प्रभारी मंत्री के अनुमोदन हेतु भोपाल प्रस्तुत की गई किंतु प्रभारी मंत्री ने सूची में कुछ नामों के लिये ही सहमति दी। बहुत से कर्मचारी जिन्होंने स्वयं के व्यय पर स्थानन्तरण हेतु आवेदन किये थे और कुछ लापरवाह कर्मचारी जिन्हें कार्यालय प्रमुख द्वारा हटाना था कुछ कर्मचारियों की स्थानीय स्तर से शिकायत के आधार पर हटाया जाना था सूची पर प्रभारी मंत्री की सहमति न मिलने से मंडला जिला के वन विभाग के स्थानीय व विभागीय कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है।

जिले में कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर कहीं भी संशय की स्थिति नहीं है यहां तो सचिव भी वर्षो से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं जिन्हें आज तक कोई हटा नहीं सका है ऐसे बहुत से विभाग हैं जहां पर वर्षो एक ही अधिकारी, कर्मचारी काम करता मिल जायेगा शायद वे स्थानांतरण नीति से परे हैं तभी तो उनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ बार-बार खबरों के प्रकाशन के बावजूद शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का टोटा इसका प्रमाण है।

जागृति श्रीवास्तव ने प्राचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण किया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

जनजातीय कार्य विभाग में लम्बे शैक्षणिक अनुभव एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवायें देने वाले श्रीमती जागृति श्रीवास्तव को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर चटुआमार मण्डला में प्राचार्य प्रथम श्रेणी के पद पर पदस्थ किये जाने के उपरान्त इनके द्धारा दिनांक 15 जून को अपना कार्यभार ग्रहण किया गया। कार्यभार ग्रहण उपरान्त इनके द्धारा विद्यालय परिसर में स्थित मां सरस्वती जी का पूजन अर्चन किया जाकर विद्यालय का निरीक्षण करते हुये शिक्षकों को अपना कार्य पूर्ण जिम्मेदारी एवं निष्ठा से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में विद्यालय का परीक्षा परिणाम शतप्रतिशत रहे इस हेतु विशेष कार्ययोजना एवं रेमेडियल क्लास लगाये जाने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। कार्यभार ग्रहण के दौरान बोर्ड परीक्षा समिति एवं विद्यालय स्टाफ के द्धारा बुके एवं पुष्प गुच्छ से नवागत प्राचार्य का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अखिलेश चन्द्रौल सेनि प्राचार्य पीएमश्री सेमरखापा, शैल कुमार दुबे सेनि प्राचार्य कन्या हाईस्कूल पुरवा, बोर्ड परीक्षा प्रभारी महेन्द्र श्रीवास, दिनेश दुबे प्राचार्य ज्ञानदीप उमावि मण्डला, मनीष दुबे प्राचार्य नवीन हाईस्कूल महाराजपुर, परीक्षा सहायक सुशील अर्सिया उमाशि जामगांव, पूर्व प्राचार्य सुशील पटैल आदर्श उमावि अंजनिया, सुदीप पटैल माशि हाईस्कूल मेढाताल, विवेक शुक्ला अध्यक्ष मध्यप्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा मण्डला एवं स्काउट सहायक जिला कमिश्नर एवं समन्वयक संस्था से विवेक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रवास | **पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का प्रथम मंडला आगमन।**

12 वर्ष सेवा एवं सुशान के स्वर्णिम अध्याय

*** कार्यकर्ताओं की ली बैठक, हुआ संवाद।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का प्रथम मंडला आगमन हुआ, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर के विभिन्न चौक-चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा एवं माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इसके पश्चात भाजपा जिला कार्यालय में ढोल-नगाड़ों के बीच उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से परिचय लिया जिसके बाद बैठक ली। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीराम पटेल, उदयप्रताप सिंह, संभाग प्रभारी धनेश धनंजय, जिला उपाध्यक्ष एवं मोर्चा संयोजक महेंद्र पटेल, जिला महामंत्री लखन बंजारा, दुर्गेश साहू, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, डॉ. विजय आनंद मरावी, पूर्व जिला महामंत्री उमेश ठाकुर एवं पूर्व प्रदेश मंत्री राजेश पटेल, नगर अध्यक्ष शिवा रानू राजपूत सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम अध्याय के रूप में देश के इतिहास में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करें। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणादायी कविता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं में राष्ट्र सेवा एवं संगठन के प्रति समर्पण का भाव जागृत किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति हावी रही, लेकिन भाजपा ने विकास, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राजनीति की नई संस्कृति स्थापित की है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार अत्यंत सरल, सहज एवं कार्यकर्ताओं के बीच रहकर संगठन को मजबूत करने वाले नेतृत्वकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश भर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठनात्मक रूप से और अधिक सशक्त होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के आगामी संगठनात्मक प्रवास एवं कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि मोर्चा द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा भाजपा की विचारधारा और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में अपर कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, कुल 112 आवेदन प्राप्त

मण्डला। जिला मुख्यालय स्थित जिला योजना भवन में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जिले के विभिन्न दूर-दराज के क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाश्वत सिंह मीना के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं और उनके निराकरण के लिए आवेदन सौंपे। जनसुनवाई के दौरान कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को संवेदनशीलता और गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने उपस्थित एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर समय-सीमा के भीतर न्यायसंगत निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

कार्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मदनपुर विकासखंड घुघरी जिला मण्डला

पत्र क /SSA/KGBV छात्रावास/2026/58 दिनांक 16/06/2026

// निविदा सूचना //

समस्त निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मदनपुर में निवासरत बालिकाओं के खाद्यान्न, किराना एवं जनरल सामग्रियों की पूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म राशि रू. 200/- में क्रय (शर्तें व नियम) करने की अंतिम तिथि 22/06/2026 शाम 05:00 बजे तक है। इच्छुक निविदाकर्ता दिनांक 25/06/2026 अपरान्ह 02:00 बजे तक बंद लिफाफा में अपनी निविदा छात्रावास कार्यालय में जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें (लिफाफे) दिनांक 25/06/2026 को दोपहर 03:00 बजे छात्रावास प्रबंधन समिति कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मदनपुर, घुघरी के समक्ष खोली जायेगी।

छात्रावास अधीक्षिका
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मदनपुर
विकासखंड घुघरी जिला मण्डला

कार्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास मैसवाही विकासखंड घुघरी जिला मण्डला

पत्र क /SSA/NSCB छात्रावास/2026/55 दिनांक 16/06/2026

// निविदा सूचना //

समस्त निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास मैसवाही में निवासरत बालिकाओं के खाद्यान्न, किराना एवं जनरल सामग्रियों की पूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म राशि रू. 200/- में क्रय (शर्तें व नियम) करने की अंतिम तिथि 22/06/2026 शाम 05:00 बजे तक है। इच्छुक निविदाकर्ता दिनांक 25/06/2026 अपरान्ह 02:00 बजे तक बंद लिफाफा में अपनी निविदा छात्रावास कार्यालय में जमा कर सकते है। प्राप्त निविदायें (लिफाफे) दिनांक 25/06/2026 को दोपहर 03:00 बजे छात्रावास प्रबंधन समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास मैसवाही, घुघरी के समक्ष खोली जायेगी।

छात्रावास अधीक्षिका
नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास मैसवाही
विकासखंड घुघरी जिला मण्डला

खबर संक्षेप

यातायात नियमों की उड़ रहीं धज्जियाँ

हरिभूमि न्यूज/ चीचली। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जहाँ भी नजर दौड़ाओ उधर ही यातायात नियम टूटते हुये नजर आ रहे हैं, कभी छोटे-छोटे बच्चे दोपहिया वाहन चलाते नजर आ रहे हैं तो कभी युवा वर्ग भी दो पहिया वाहनों पर तीन से लेकर चार सवारी बैठाकर फर्राटे मारते सामने से निकलते हुये देखे जा सकते हैं, इतना ही नहीं कभी काल पुलिस द्वारा चैकिंग की औपचारिकता निभाई जाती है तो मात्र कागजों की खानापूर्ति कर सौ पचास में समझौता कर वाहनों को छोड़ दिया जाता है, यदि पुलिस अपनी जागरूकता दिखावे तो लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है मगर जहाँ तहाँ नाबालिगों द्वारा दौड़ाये जा रहे वाहनों को देखकर तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस को नगर की यातायात व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर नगर में जीपों व मैजिक गाडियों को ट्रैक्टर ट्रालियों में किस तरह सामान लाद कर व सवारी भरे दौड़ाये जा रहे है यह क्षेत्र की सड़कों पर आसानी से देखा जा सकता है जिसका जीता जागता उदाहरण क्षेत्रों के मार्ग पर देखने को मिलता है, जो प्रतिदिन पुलिस की ड्यूटी व्यवस्था के बाद भी पुलिस के नुमाइंदों के सामने से गुजर रहीं हैं और वे देखते रह जाते हैं,जनापेक्षा है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे।

गांव गांव फैल रहा है अनेक प्रकार की निजी फाइनेंस कंपनियों का गोरखधंधा

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। इन दिनों देख जा रहा है कि क्षेत्र के गॉवों मे अनेक निजी फाइनेंस कम्पनियों से जुड़े हाईटेक युवकों की रेडी उतर आयी है जो छोटे धंधों की शुरूआत के लिए ग्रामीण महिलाओं को ऋण देने का आश्वासन देकर अपने प्रलोभन के जाल मे गॉवों की भोली भाली अशिक्षित महिलाओं को फॅसाकर बड़े मीठे अंदाज मे उनका आर्थिक शोषण कर रहे है,हासिल जानकारी के अनुसार क्षेत्र के आसपास अनेक गांवों मे लम्बे समय से एक तथा कथित फाइनेंस कम्पनी से सम्बंधित कुछ युवक गॉव की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाते हुए उन्हे ठगने की लगातार कोशिश कर रहे है? ज्ञात हुआ है कि उक्त कंपनी की तरफ से पति पत्नी की साथ फोटो प्रस्तुत करने पर महिलाओं को धंधा शुरू करने के लिए 8 हजार रू. लोन दिया जाता है तथा ऋण लेने वाली ग्रामीण महिला से हर हप्ते 20 रू. बीमा की राशि वसूल की जाती है? सूत्रों के अनुसार इस फाइनेंस कम्पनी से जुड़े लगभग 18-20 वर्ष के युवक हर सप्ताह ग्रामीण महिलाओं की बैठक भी करते है, जिसमें वे महिलाओं को लच्छेदार भाषा मे समझाते है कि छोटा व्यापार कर ग्रामीण महिलाएँ काफी धन कमा सकती है। विदित हुआ है कि ग्रामीण महिलाएँ इन युवकों की बाते सुनकर विभोर होकर अपने लड़कों की उम्र के फायनेंस कम्पनी के युवकों को सर कहने लगती है और उनसे ऋण लेने तैयार हो जाती है, जागरूक ग्रामवासियों के अनुसार असल मे निजी फायनेंस कम्पनी का सारा नेटवर्क शोषण के आधार पर टिका है और 5 वर्ष मे ऋण लेने वाली महिलाएँ काफी आर्थिक नुकसान मे पड़ जायेगी? उल्लेखनीय है कि पूर्व मे भी क्षेत्र मे निजी फायनेंस कम्पनियों के गोरखधंधें की बहुत सी शिकायते सामने आयी थी? लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक प्रशासन ने इन कम्पानियों की कारगुजारियों पर अंकुश लगानें की पहल नही की है।

वर्षो पुरानी बिजली लाईनों के भरोसे चल रही अटल ज्योति योजना से परेशान हो रहे ग्रामीण

हरिभूमि न्यूज/ पलोहा बड़ा। जिस प्रकार से शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली देने की बात कहते हुए अटल ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया था जिसके चलते जहां लोगों में खुशी देखने मिल रही थी, मगर यह योजना इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से वर्षो पुरानी बिजली लाईनों में चलते हुए देखी जा रही है उसके चलते ग्रामवासियों को सिर्फ परेशानी ही नही बल्कि इस योजना के तहत 24 बिजली मिल पाना मुश्किल हो रहा है? बताया जाता है कि इस योजना के तहत जिस प्रकार से सिंचाई हेतु अलग वह घरेलू उपयोग हेतु अलग अलग बिजली लाईनों का विस्तार करने के लिए निजी कंपनियों को ठेका देते हुए कार्य कराया गया था। मगर बिजली लाईनों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों द्वारा पुराने ही बिजली तारों के माध्यम ही इस योजना को स्वरूप बढते हुए कम बोल्टेज वाले तारों पर हाई बोल्टेज की सप्लाई कर दी गई है जिसके चलते स्थिति इस प्रकार से निर्मित होते हुए देखी जा रही है कि वर्षो पुराने यह तार जहां हाई बोल्टेज को सहन नही कर पा रहा है।

कुछ साल पहले ही निर्मित सूखाखैरी से बारहाबड़ा होते हुये सालीचौका सीमेन्ट सड़क गड्ढों में हुई तब्दील, पुलियों के बीच निकल रही लोहे की राड बजा रही मौत का सायरन

हरिभूमि न्यूज/ बारहाबडा।

भले ही देश व प्रदेश में बैठे हुये नेताओं द्वारा लगातार बढ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये कितने ही प्रयास क्यों न किये जावे। मगर यदि प्रशासन तंत्र में बैठे हुये छोटे से लेकर बड़े अधिकारी शामिल हो तो शायद ही इस पर अंकुश लग पाना संभव नही हो पता है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय ग्राम सूखाखैरी से होते हुये बारहाबड़ा से निकलकर सालीचौका पौड़ार तिरहा तक लगभग 76 करोड़ रूपया की राशि से चंद वर्ष ही पहले बनाई गई सीमेन्ट सड़क में देखने मिल रहा है..? बताया जाता है कि इस सड़क का निर्माण कार्य हुये अभी ज्यादा लम्बा समय नही निकला है। मगर यह सीमेन्ट सड़क जहां तहां जिस तरह टूटते हुये पुलियों के बीचों बीच निकल रही लोहे की राडे वाहन चालको की जिन्दगी को खतरा पैदा तो कर ही रही है दूसरी ओर इस सड़क के निर्माण कार्य में अपनाई गई गुणवत्ता की कहानी को उजागर करने से नही चूक रही है? वही दूसरी ओर इस सड़क निर्माण से संबंधित उन अधिकारियों की पोल भी खुलने से नही चूक पा रही है कि आखिरकार उनके द्वारा जिस आधार पर इस सड़क निर्माण कार्य को लेकर अपनी संतुष्टि प्रदान करते हुये कार्य को सही बताते हुये निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को भुगतान कर डाला है..? जबकि सच्चाई पर गौर किया जावे तो करोड़ो की राशि से बनाई गई इस सीमेन्ट सड़क के निर्माण के दौरान ही जिस तरह गफलत बाजी दिखाई देना शुरू हो गया था। उस सच्चाई को को हरिभूमि द्वारा लगातार प्रमुखता के साथ उजागर किया गया था। मगर इसके बाद भी इस ओर किसी भी अधिकारी द्वारा ध्यान देना उचित नही समझे जाने से लग रहा है कि शायद लक्ष्मी पूजन के आर्शीवाद के चलते अधिकारी भी मग्न हो चुके है? वैसे भी यदि इस सड़क निर्माण कार्य की सच्चाई पर गौर किया जावे तो शुरूआती तौर से ही इस सड़क के निर्माण कार्य में अपनाई जाने वाली गुणवत्ता पर सबाल खड़े होने लगे थें? जब सड़क के निर्माण कार्य की शुरूआत करते हुये वक्त कुछ पुलियों का निर्माण कार्य ही हो पाया था कि और ग्राम बारहाबड़ा के पास निर्माणाधीन एक पुलिया निर्माण के दौरान ही धराशाही हो जाने के कारण उसमें काम करने वाले कुछ मजदूरों को चोटे भी आई हुई थी। वही दूसरी ओर इस सीमेन्ट सड़क निर्माण के दौरान की धराशाही हुई पुलिया ने जहां सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सबाल खड़े कर दिये गये थें। इस प्रकार से सड़क निर्माण कार्य में अपनाई जाने वाली गुणवत्ता की कहानी को हरिभूमि द्वारा लगातार उजागर करते हुये संपूर्ण सच्चाई से अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है। मगर कहा जाता है कि जहां लक्ष्मी पूजन का प्रभाव होता है वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों को भी आम के पेड़ में इमली लगी हुई दिखाई देने से नही चूक पाती है और शायद यही हाल इस सड़क के निर्माण कार्य की देख रेख में लगे हुये जिम्मेदार अधिकारियों का देखने मिला है जो सड़क निर्माण कार्य में अपनाई जाने वाली गुणवत्ता को निर्माण के दौरान पूर्णरूप से नजर अंदाज करते हुये निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को अपनी ओर से छूट प्रदान करने से नही चूक होगे जिसके चलते यह सड़क जहां निर्माण के दौरान ही जहां तहां से टूटते हुये नजर आने लगी थी और इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को अपनी ओर से प्रदान किये गये संतुष्टि प्रमाण पत्र के चलते निर्माण कार्य का भुगतान हो गया और अपने निर्माण के चंद यानि की मात्र दो तीन साल के अंदर ही यह सड़क जहां तहां से टूटने के साथ पुलियों की और निकल रही लोहे की राड़े वाहन चालकों की जिन्दगी को खतरा पैदा करने से नही चूक रही है। बताया जाता है कि जब सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था उसी समय ग्राम बारहाबड़ा से सूखाखैरी के बीच इस सड़क के निर्माण के दौरान एक पटरी का कार्य ही हो पाया था और दूसरी पटरी का निर्माण कार्य होना शेष था और सड़क टूटना शुरू हो गया था। इस प्रकार से सही मायने में देखा जावे तो इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण भी नही हो पाया था और ग्राम बारहाबड़ा से सिंहपुर छोटा तथा ग्राम आंडेगांव व सूखाखैरी के बीच निर्मित सड़क ही अनेक जगहों से टूटते हुये दिखाई देने लगी थी। इस सच्चाई को उस समय हरिभूमि द्वारा लगातार उजागर किये जाने के बाद भी न तो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया गया था और न ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिसका परिणाम है कि लगभग 76 करोड़ की लागत से बनी हुई इस सड़क मात्र चार दिन की चांदनी फिर अधियारी रात साबित होने से नही चूक रही है? अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि जिस सोच के चलते क्षेत्र के जिम्मेदार नेताओं द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों की सुविधाओं को ध्यान को रखते हुये दिन रात एक करते हुये इस सड़क को स्वीकृत कराने के बाद शासन द्वारा इस सड़क निर्माण के लिये करोड़ो रूपया खर्च करने में कोई कसर नही छोड़ी गई थी। मगर संबंधित विभाग से जुडे हुये अधिकारियों से लेकर निर्माण कार्य करने वाली कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के नाम पर जिस प्रकार शासकीय धन की होली खेलते हुये सड़क का निर्माण कार्य किया था और वह सड़क जब अपने निर्माण के मात्र दो तीन वर्ष भी नही चल सकी तो फिर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि इस सड़क के निर्माण में हुई गफलत की मलाई में कितने हिस्सेदार रहे होगे की लगातार आवाज उठाये जाने के बाद भी किसी तरह की कार्यवाही नही हो सकी और करोड़ो की राशि की खुलेआम होली खिल जाने के कारण क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करते हुये अपनी जिन्दगी को खतरे में डालने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है? यदि सड़क निर्माण में अपनाई गई गुणवत्ता की निष्ठा के साथ जांच कराई जावे तो निश्चित तौर से चौकाने वाली सच्चाई उजागर होने से नही चूक पायेगी और इस विभाग के जुडे हुये उन अधिकारियों से लेकर क्षेत्र की छुटभैया नेताओं के चेहरे भी उजागर हो जावेगे जो इस प्रकार गुणवत्ता को दर किनार सड़क निर्माण का कार्य करने वाली कंपनी को अपना अघोषित रूप से संरक्षण देने से नही चूके है? इस प्रकार से सरकार के लगभग 76 करोड़ रूपया की राशि से निर्मित होने वाली इस सड़क जिस प्रकार से अपने निर्माण के मात्र दो वर्ष बाद ही टूटना शुरू हो गई है उसकी गुणवत्ता को लेकर जांच कराई जाने की मांग उठाई जा रही है।

हूटर लगी गाडियों का खुलेआम हो रहा दुरूपयोग, प्रशासन के नजरअंदाज किये जाने के कारण हो रहे नगरवासी परेशान?

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा।

इस समय नगर में आये दिन देखने मिल रहा है कि लोगों द्वारा जहां अपने वाहनों में मनमाने तौर से प्रशर हार्न लगाकर ध्वनि अधिनियम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? वही दूसरी ओर अनेक लोगों द्वारा अपने चार पाहिया वाहनों में यातायात नियमों को दर किनार करते हुए हूटर लगाकर मनमानी पर उतारू देखे जा रहे है? मगर इस सब में मजेदार बात तो यह है कि इस प्रकार से मनमान तौर से हूटरों का हो रहे दुरूउपयोग को लेकर स्थानीय शासन प्रशासन पूर्ण रूप से नजर अदांज कर रहा है, जिसके चलते नगर में अनेक वाहनों में खुलेआम हूटर देखने मिल सकते है, जबकि हूटर लगाने के लिए मा. न्यायालय व परिवहन विभाग द्वारा नियम कानून बनाये गये है, जिनकी खुलेआम आब्हेलना की जा रही है? वही वाहनों में हार्न लगाने के लिए भी लोगों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है, लोगों के वाहनों में लगे हूटर व हार्नो से राहगीरों के लिए परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, वही स्कूल वाहनों में लगे प्रेशर हार्न से स्कूली बच्चों पर विपरित प्रभाव देखने मिल रहा है। यदि सच्चाई पर गौर किया जावे तो क्षेत्र के कुछ नेताओं द्वारा भी अपने वाहनों में हूटर लगाकर नियमों की अनदेखी करते हुए आये दिन वाहनों के पीछे पुलिस सायरन वाला हूटर बजाकर रौब झाडा जाता है, और जब यह तेज हूटर रात के समय नगर में बजाया जाता है तो सोने वाले लोगों की नीद खराब हो जाती है, मगर धन्य है नगर का पुलिस प्रशासन जो आये दिन दुकानदारों सहित अन्य गरीब मजदूरों के बीच पहुंचकर उन्हे अपनी बर्दी की ताकत दिखाने के लिए तो हड़कता रहता है? मगर जिस प्रकार से लोगों द्वारा खुलेआम शासन के नियमों की अब्हेलना की जा रही है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नही करता है।

शहर में जलाऊ लकड़ी का गहराया संकट, गैस के कीमत में हुई वृद्वि के चलते दो वक्त की रोटी बनाना हो रहा है मुश्किल

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा।

म.प्र.शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जहां शहर के गरीबो में जो आशा की किरण झलकी थी। मगर उसकी झिलमिल रोशनी को लगता है कि चल रहा गर्मी के मौसम व बारिश के आगमन के बीच ग्रहण लगने से नही चूक पा रहा है..? हालत यह है कि गरीबो को जरूरत के हिसाब से सहकारी दुकानो से सस्ती दर पर गेहूँ, चॉवल, नमक तो ठीक समय पर आवंटित किये जा रहे है। मगर शक्कर की मिठास शासन की योजना के तहत गायब ही हो चुकी है...? वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि इस समय जलाऊ लकड़ी, कैरोसिन का संकट गहराने से गरीबो को घरो में दो वक्त चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। नगर के अनेक वार्डो के गरीबो ने बताया कि उनके घरो में रसोई गैस की व्यवस्था तो सरकार की उज्जबला योजना के तहत हो गई है। मगर इस महगांई के दौर में जहां गैस भरवाना आसान नही रहे गया है। इस स्थिति में लकड़ी ही उनका सहारा बनती थी जिसके चलते घरो की गृहणियॉ खाना तैयार करने के लिए जलाऊ लकड़ी पर निर्भर रहती है या फिर उन्हे स्टोव का सहारा लेना पड़ता हैद्ध मगा मिट्टी तेल के दर्शन होना मुश्किल हो गया है। वही दूसरी ओर नगर में गौर किया जावे तो यह अजीब बात है कि इन दिनों शहर में जलाऊ लकड़ी आना बंद ही हो चुका है और यदि कभी काल आती भी है तो वह काफी मॅहगी बिक रही है। इसके चलते गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को टालो में जलाऊ लकड़ी खरीदने पर उसकी कीमत सुन गरीबों के होश उड़ रहे है। इन गरीबों का कहना है कि पहले वनांचल के गांवो से आदिवासी महिलाएँ, पुरूष जलाऊ लकड़ी के गट्ठे लाकर झंडाचौक और शहर के विभिन्न स्थानो पर बेचते थे, इन गट्ठो को खरीद गरीब अपना काम चला लेते थें। लेकिन लम्बा समय बीतने के बाद भी जंगल पट्टी के गांवो से आदिवासी बहुत कम जलाऊ लकड़ी ला रहे है, जिसके कारण जलाऊ लकड़ी का एक गट्ठा 400 रू. से लेकर 500 रू.तक बिक रहा है? इन गट्ठो में इतनी ही लकड़ी रहती है, जिसका इस्तेमाल इंधन के रूप में गरीब सिर्फ 2-3 दिन कर सकते है। इसके बाद फिर उन्हे जलाऊ लकड़ी की विकराल समस्या से जूझनें मजबूर होना पड़ता है। अधिकतर गरीबो ने बताया कि चल रहे मौसम में सहकारी दुकानों से उन्हे जो कैरोसिन उपलब्ध होता है वह जलाऊ लकड़ी के अभाव में स्टोव जलाने में पूरा नही होता। इसलिए कभी कभार गरीबो को काला बाजारी के माध्यम से मिट्टी का तेल खरीदने विवश होना पड़ता है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई उज्जबला योजना के तहत जिन लोगों को गैस प्रदान की गई है उन लोगों को सहकारी दुकानों से कैरोसिन देना बंद कर दिया गया है। क्योंकि गैस से पूरे परिवार का भोजन तैयार करने में चंद दिन में ही समाप्त होने के कारण उन्हें मजबूरी बस मिट्टी तेल या फिर लकड़ी का सहारा लेने मजबूर होना पड़ रहा है। मगर सहकारी दुकानों से मिट्टी तेल नही मिलने की स्थिति में वह परेशान हो रहे है? सूत्रो के अनुसार इन दिनों जलाऊ लकड़ी की कमी के दौरान मिट्टी के तेल की कालाबाजारी को खेल नगर में चलने लगा है, जिससे गरीबो को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गरीबो की माने तो क्षेत्र के जंगल पट्टे के गांवो से जो आदिवासी बच्चे, महिलाएँ लकड़ी के गट्ठे लाते है उन्हे काफी खर्च झेलना पड़ता है, जिससे स्वाभाविक तोर पर वे कम जलाऊ लकड़ी शहर ला पा रहे है और नगर में जलाऊ लकड़ी की कमी के हालात बन गए है। इसी के चलते शहर के गरीबो ने प्रशासन से गुहार लगायी है कि गरीबो को वन विभाग के डिपो और टालो से नियंत्रित दर पर जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था तत्काल की जाए ताकि शबाब पर आ रही गर्मी के मौसम के दौरान उनके घरो में दो वक्त चूल्हे जल सके। क्योंकि सरकार द्वारा हर प्रकार की सामग्री के बीच गैस के दामों में किये गये इजाफे के चलते अब दो वक्त की रोटी मुश्किल होने लगे है। कहने के लिये तो लाड़ली बहनों को कम दामों पर गैसे उपलब्ध कराई जा रही है। मगर यह सच्चाई किसी से छुपी नही है। अधिकांश लोगों के घरों में गैस कनेक्शन उनके पतियों के नाम पर होने के चलते लाड़ली बहना गैस का लाभ उन परिवारों को नही मिल पा रहा है और वह निर्धारित दाम पर ही गैस खरीदने के लिये मजबूर होते हुये देखे जा रहे है।

नगर की नालियों पर पैसे वालों का कब्जा, अतिक्रमण मुहिम के बाद भी मुक्त नहीं हो पा रही है नालियां?

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा।

आये दिन देखा जाता है कि प्रशासन द्वारा नगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम तो चलाई जाती है। मगर उस अतिक्रमण की सच्चाई पर गौर किया जावे तो वह मात्र औपचारिता ही साबित होते हुए सिर्फ छोटे मोटे गरीबों के घर तोड़ने तथा टपरे हटाने तक सीमित रह जाती है? क्योंकि जिस प्रकार से प्रभावशाली लोगों द्वारा अपना अतिक्रमण किया गया है वह तोड़ने में शायद प्रशासन द्वारा संकोच बरती जाती रही है जिसकी सच्चाई इस समय नगर में जहां तहां आसानी से देखने मिल सकती है? इस प्रकार से अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाकर जिन लोगों के कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाये गये थें। वह लोग पुनः उसी जगहो पर कबीज नजर आते हुए दिखाई पड़ रहे है। वही दूसरी ओर गौर किया जावे तो गरीबों के अतिक्रमण हटाने मे बहादुरी दिखाने वाला प्रशासन का अतिक्रमण दस्ता पूंजी पतियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने मे बेबस नजर जान पड़ रहा है? क्योंकि यदि नगर के अतिक्रमण की सच्चाई पर गौर किया जावे तो नगर में अनेक जगहों पर जहां लोगों द्वारा नजूल की जमीन एवं मेन रोड के बगल से नाले व नालियों को अतिक्रमणकारियों द्वारा पूर्णरूप से उन्हें ढ़ककर उसके ऊपर कोटा स्टोन एवं मार्बल लगाते हुए अपने कब्जे में कर लिया गया है जिसके चलते जहां स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करने मजबूर होना पड़ रहा है? इस बात की सच्चाई का प्रमुख नजारा इस समय नगर के प्रमुख बाजार के साथ नगर की गालियों एवं कुछ अन्य स्थानों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर कई वर्षो से इन धनवानों ने नजूल की जमीन एवं नाले नालियों को बंद कर अपनी जागीर बना रखा है। नगर के नाले नालियों के पास रहनें वाले लोगों के निस्तार के पानी का मार्ग इससे अवरूद्ध होता जा रहा है और व्याप्त गंदगी से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बन रही है? वही दूसरी ओर गौर किया जावे तो नगर के बस स्टेन्ड से पलोहा नाका की ओर जाने वाले प्रमुख चौराहे की स्थिति तो इस प्रकार से देखने मिल रही है कि लोगों द्वारा जिस प्रकार से अपने भवनों को निर्धारित सीमा से बढ़ाकर आगे की ओर बनाया गया है उससे सड़क का हाल यह बन चुका है कि वहां पर बसों के निकलने में इतनी परेशानी होती है कि बस चालक इस दहशत में रहते है कि कोई घटना घटित न हो जावे। जबकि यहां के मार्ग को काफी चौड़ा बताया जा रहा है, मगर अतिक्रमण की बाढ़ के चलते यहां पर छोटे वाहनों का निकलना तक मुश्किल हो चुका है। यह बात अलग है कि इस समय प्रशासन द्वारा नगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई चलाई जाती है। मगर यह मुहिम मात्र गरीबों तक सीमित रहने के कारण धनवानों की हवेलियों में आज भी शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए अपनी खुशी की किलकारी दिखाई पड़ रही है जिसके चलते शासन के ईमानदारी से अतिक्रमण हटाने की सच्चाई पर पक्षपात के बादल स्पष्ट मडराते हुए दिखाई पड़ रहे है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम आने का इंतजार करते करते गिरने लगे गरीबों के बच्चे मकान

हरिभूमि न्यूज/ सांईखेड़ा। इस बात से इंकार नही किया जा सकता है कि जिस सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को पक्के मकान देने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की गई है उसके चलते उन गरीबों को पक्के आवास मिलते हुये देखे जा रहे है जो कभी पक्के मकानों में रहने का सपना भी नही देख सकते थें? मगर इस योजना का सांईखेड़ा क्षेत्र के अनेक गांवों में सही रूप से क्रियान्वयन नही होने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना अपने लक्ष्य से भटकते हुये दिखाई देने लगी है? इस कारण से जहां साधन संपन्न लोगों के आवास तो बनते हुये देखे जा रहे है। मगर इस योजना के जो वास्तविक गरीब हितग्राही है वह आज भी इस योजना में शामिल होने के लिये इंतजार करते हुये अपने कच्चे आवासों में मौत और जिन्दगी के बीच जीवन काटने के लिये मजबूर होते हुये दिखाई देने से नही चूक पा रहे है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय जनपद पंचायत सांईखेड़ा के अंतर्गत आने वाले अनेक ग्राम पंचायतों में देखने मिल रही है जहां पर इस प्रकार के दर्जनों गरीब है जिनके कच्चे मकान होने के बाद भी अभी तक उनका प्रधान मंत्री आवास योजना की सूची में नाम नही आने की स्थिति में उनके कच्चे मकान गिरने की हालत में पहुंच जाने कारण मासूम बच्चों की जिन्दगी खतरे में दिखाई देने से नही चूक रही है। इस संबंध में खस्ता हाल कच्चे मकानों में जीवन यापन करने वाले गरीबों द्वारा जानकारी देते हुये बताया है कि वह पूर्णरूप से गरीब होने के साथ साथ उसकी स्थिति इस प्रकार से नही है कि वह अपना कच्चा मकान पक्का कर सके, जिसके चलते प्रधानमंत्री की आवास योजना सूची में नाम आने का इंतजार करते हुये लम्बा समय बीत जाने के बाद भी नाम नही आने के कारण कच्चे मकान का हाल इस स्थिति में पहुंच चुका है कि उसकी दीवारे चारों ओर से गिरने की शुरूआत होने के कारण यह डर सताने लगा है कि कही ऐसा न हो कि रात के समय पूरा का पूरा मकान धराशाही होने के कारण उसकी व उसके मासूम बच्चों की जिन्दगी खतरे में पड़ जावे, इस प्रकार से अन्य लोगों के आवासों की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से बनी हुई है जिनके कच्चे मकानों की गिरती हुई दिवारे निश्चित ही इस प्रधान मंत्री आवास योजना को अपने लक्ष्य से भटकने का उदाहरण देने से नही चूक पा रही है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के हितग्राहियों के मशीन में फिंगर नहीं आने से हो रहे परेशान

हरिभूमि न्यूज/ सांईखेड़ा।

शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाकर वृद्धों एवं गरीबों का भला करने की बात कही जा रही है वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं व पुरूषों की हालत दिन पर दिन दयनीय व पीड़ा दायक होती जा रही है। यह बात अलग है कि इस हेतु शासन ने वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की थी मगर शासन की इस योजना को पंचायत में बैठे कर्णधारों द्वारा शासन के नियमों को अनदेखा कर पात्रजनों को इसका लाभ ना देकर अपात्रों को दिया जा रहा है और इसी प्रकार शासन की कई अन्य योजनायें भाई-भतीजावाद की शिकार हो रही हैं जिसके कारण आज इन वृद्धों को शासन की अनेक योजनायें चलने के बाद भी भूखों रहने की नौबत आ रही है। शासन द्वारा वृद्धों के लिये वृद्धावस्था सुरक्षा पेंशन का फार्म निकालकर यह नियम लागू किया गया था। मगर इस योजना का लाभ अनेक निःसहाय वृद्धों को नहीं मिल पा रहा है? आम जन का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा इन वृद्धों के आवेदनों को बिना देखे ही निरस्त कर दिया जाता हैं, विधवा महिलाओं की भी स्थिति अत्यंत दयनीय रहती है। देखने में आता है कि उन्हें भी शासन की योजनाओं से कोई फायदा नहीं मिल पाता है। क्षेत्र में अनेक विधवा महिलायें हैं जो परेशानियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं जिनका भला करने के उद्देश्य से शासन ने इस प्रकार की योजनायें शुरू की थी मगर देखा जा रहा है कि शासन द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की अनेक योजनाओं के बारे में पंचायत स्तर पर बैठे कुछ अधिकारी भाई-भतीजावाद की भेंट चढ़ाकर उन्हें पूरा कर देते हैं और पात्र हितग्रहियों को उनसे वंचित कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि नगर परिषदों से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा इन योजनाओं की राशि अनेकों माह तक बैंकों में ही पड़ी रहती है और हितग्राही इस राशि को पाने के लिये भटकते रहते हैं। क्योंकि शासन की योजना के तहत इन वृद्वों की पेंशन राशि का भुगतान के लिये उनके खाते आधार से लिंग किये गये है। मगर अनेक वृद्वजनों के अब भुगतान मशीन में फिंगर सही रूप से नही आने के कारण पेंशन राशि के भुगतान से बंचित हो रहे है। इस प्रकार से वृद्वजनों की बीते हुये कई महिनों से पेंशन राशि बैक खातों में ही पड़ी है और उसका हितग्राही कोई लाभ नही ले पा रहे है।

जनसुनवाई में ग्रामीणों ने उठाई नई पंचायत और सड़क निर्माण की मांग

डिंडौरी। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में कुल 93 आवेदन प्राप्त हुएए जिनमें संबल योजना की सहायता राशिए अनुग्रह सहायताए विद्युत बिल संबंधी शिकायतेंए सड़क निर्माणए नई ग्राम पंचायत गठनए आवागमन मार्गए आगजनी से हुए नुकसान के मुआवजे तथा शासकीय योजनाओं में अनियमितताओं से जुड़े मामले प्रमुख रहे।जनसुनवाई के दौरान ग्राम अमरपुर निवासी जयंती धूमकेती ने आवेदन देकर बताया कि उनके पति अनिल कुमार धूमकेती का वर्ष 2024 में निधन हो गया था। संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि के लिए आवेदन करने के बावजूद उन्हें अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की।

इस पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए।
वनग्राम हथकटा के ग्रामीणों ने अपनी बस्ती को वर्तमान ग्राम पंचायत परसेल से पृथक कर नई ग्राम पंचायत गठित किए जाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत मुख्यालय की दूरी अधिक होने और बीच में वन क्षेत्र होने के

कारण विकास कार्यों एवं प्रशासनिक सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।ग्राम गीधाए तहसील बजाग निवासी मनोज कुमार राजपूत ने अत्यधिक विद्युत बिल जारी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।इसी प्रकार वनग्राम देवकरा के ग्रामीणों ने गांव तक सड़क मार्ग नहीं होने से आवागमन में होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। ग्रामीणों ने विशेष रूप से वर्षाकाल में स्कूली बच्चों को आने.जाने में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए सड़क निर्माण की मांग की। इस पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हनुमान टेकरी निवासी रेखा मरावी ने विद्युत शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने के कारण हुए नुकसान पर मुआवजा एवं आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की।
जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर जेण्पीण यादवए डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिकए संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावीए एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगनए महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्याम सिंगौरए एनआरएलएम प्रबंधक अर्पणा पाण्डेयए कोषालय अधिकारी डीण्एनण हजारियाए जिला शिक्षा अधिकारी सुमन परस्ते सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

कोयला भरे ट्रक मोड पर आमने-सामने टकराए, 4 घंटे तक आवागमन रहा प्रभावित

अनूपपुर। जिला मुख्यालय में मंगलवार को कृषि उपज मंडी मोड़ के समीप कोयला परिवहन कर रहे दो ट्रक आमने-सामने टकरा गए। जिससे सड़क पर लगभग 4 घंटे तक यातायात जाम की स्थिति बन गई। इसके बाद क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से किनारे किया गया तब जाकर के यातायात बहाल हो पाया। जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय में चचाई मार्ग पर ट्रक क्रमांक सीजी एनएक्स 1419 जो की चचाई की तरफ से अनूपपुर की ओर आ रहा था वहीं सामने से कोयला भर कर ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीआर 9890 अनूपपुर से चचाई रोड की ओर जा रहा था दोनों ही वाहन तेज रफ्तार में होने के कारण कृषि उपज मंडी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिससे लगभग 4 घंटे तक मुख्य मार्ग पर दोनों वाहनों के खड़े होने से यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलने के बाद यातायात और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैकों को सड़क से हटाया गया। इस दौरान छोटे वाहन साइड से निकलते रहे लेकिन बड़े वाहन यातायात जाम में फंसे रहे।

चित्रकूट धाम से आए 72 वर्षीय संत शवासन मुद्रा में मड़फा तालाब सामतपुर में 2 घंटे पानी में करेंगे योग

अनूपपुर। योग साधक संत रामसखा पांडेय चित्रकूट धाम अनूपपुर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में रुके हुए हैं। जो कि आज प्रातः 11.00 बजे से शवासन मुद्रा में मड़फा तालाब सामतपुर में 2 घंटे पानी में योग करेंगे। जिसके लिए उन्होंने नगर पालिका, पुलिस अधीक्षक एवं कोतवाली को पत्र देकर जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी अनूपपुर के पुजारी ब्रह्मानंद गर्ग ने बताया कि संत जी उनके मंदिर पर रुके हुए हैं और आज वह 2 घंटे सामतपुर तालाब में पानी के ऊपर योग कर लोगों को योग की शिक्षा देंगे। योग साधक रामसखा पांडेय ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली में इंसान लगातार तनाव और बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में योग ही एक ऐसा साधन है, जो तन-मन को संतुलित कर हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। योग साधक रामसखा पांडेय ने बताया कि वे देशभर में भ्रमण कर योग की शक्ति का संदेश दे रहे हैं।

प्रवेश उत्सव में शामिल हुईं कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, आंगनबाड़ी केंद्र मुड़की.1 का किया निरीक्षण

डिंडौरी। जिले में स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 से 30 जून तक आयोजित किए जा रहे प्रवेश उत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने आंगनवाड़ी केंद्र मुड़की.1 पहुंचकर प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता की तथा केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।इस दौरान कलेक्टर ने बच्चोंए अभिभावकों और महिलाओं से संवाद कर शिक्षाए पोषण एवं स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रवेश उत्सव का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़कर उसके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखना है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति

सुनिश्चित करने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध पोषणए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सेवाओं का लाभ लेने की अपील की।
कलेक्टर ने कहा कि माता.पिता बच्चे की पहली पाठशाला होते हैं और उनके मार्गदर्शन से ही बच्चे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दियाए ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिला सफीना बेगम की पारंपरिक गोदभराई रस्म संपन्न कराई गई। कलेक्टर ने केंद्र में संचालित गतिविधियों का अवलोकन करते हुए हितग्राहियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।जानकारी के अनुसारए आंगनवाड़ी केंद्र मुड़की.1 में 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के 32 तथा 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 38 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं केंद्र में 5 गर्भवती एवं 3 धात्री महिलाएं भी पंजीकृत हैं। सभी पात्र गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।प्रवेश उत्सव के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांशु चौधरी ने प्राथमिक शाला रूषा तथा अपर कलेक्टर जेण्पीण यादव ने प्राथमिक शाला घानामार में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी अलग.अलग विद्यालयों में पहुंचकर प्रवेश उत्सव कार्यक्रमों में सहभागिता की।इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कृष्णा बर्मनए सहायिका पार्वती धुर्वेए सेक्टर पर्यवेक्षक शारदा मार्कोए सहायक संचालक सुश्री वंदना धुमकेती सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक आयोजित, विभिन्न वर्गों से लिए गए सुझाव

डिंडौरी। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता ;यूसीसीद्ध के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनसुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जनपरामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह ने की। इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गोंए जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से सुझाव और विचार आमंत्रित किए गए।बैठक में कलेक्टर अंजू पवन भदौरियाए संयुक्त आयुक्त जबलपुर आईएएस कविता बांटलाए पुलिस अधीक्षक आशीष खरेए जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए बुधपाल सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद.44 में किया गया है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानताए न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विवाहए तलाकए भरण.पोषणए उत्तराधिकार एवं दत्तक ग्रहण जैसे विषय अलग.अलग व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत संचालित होते हैंए जबकि यूसीसी इन विषयों पर एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की अवधारणा पर आधारित है।उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉण भीमराव अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया था। समाज और समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों में परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है। शासन नागरिकों के सुझावों के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
बुधपाल सिंह ने बताया कि जो नागरिक बैठक में शामिल नहीं हो सके हैंए वे

शासन द्वारा निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से भी अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने सभी वर्गों से सकारात्मक एवं रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता में अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किए जाने का विषय विचाराधीन है।कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि प्रदेश शासन जनभागीदारी के माध्यम से नीति निर्माण को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जनपरामर्श प्रक्रिया संचालित कर रहा है। उन्होंने जिले के नागरिकों से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय एवं सुझाव देने तथा जनपरामर्श प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू ब्यौहारए नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारसए जनपद अध्यक्ष आशा सिंहए रूपाली जैनए अवध राज बिलैयाए रजनीश राय सहित अनेक जनप्रतिनिधिए अधिकारी.कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना बनी सहारा किसान परिवार को मिली 4 लाख की सहायता

डिंडौरी। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत जिले के एक किसान परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता विकासखंड बजाग के ग्राम परसवाह निवासी दिवंगत किसान चैनसिंह के निधन के बाद उनके परिवार को आर्थिक संबल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई।जानकारी के अनुसारए मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा दिवंगत किसान की पत्नी श्रीमती चमेली बाई के नाम चार लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई। मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने श्रीमती चमेली बाई को सहायता राशि का चेक सौंपा।इस अवसर पर कलेक्टर ने परिवार को राशि का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उनके नाम से एक.एक लाख रुपये की सावधि जमा ;एफडीद्ध कराई जाए तथा शेष राशि शिक्षा एवं अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च की जाए। उन्होंने अनावश्यक खर्च से बचते हुए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कृषकों की दुर्घटना अथवा असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवारजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में किसान परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें संबल देना है।

वैध रेत परिवहन पर बिजुरी पुलिस की कार्रवाई

बिजुरी। बिजुरी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 16 जुन को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से अवैध रेत परिवहन की सटीक सूचना मिली। बिजुरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धनिया ठेला तिराहा पर घेराबंदी की। इस दौरान बहेराबांध से बिजुरी की ओर आ रहे एक बिना नंबर के लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोका गया। ट्रैक्टर चालक प्रमोद अगरिया उम्र 20 वर्ष पिता रमेश अगरिया, निवासी बहेराबांध से जब रेत के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज और रॉयल्टी रसीद मांगी गई, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। चालक ने बहेराबांध से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन करना स्वीकार किया, जिसके बाद गवाहों के समक्ष ट्रैक्टर मय रेत भरी ट्राली को जब्त कर लिया गया।

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से किसान परेशान

अमरपुर। उपतहसील कार्यालय अमरपुर के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से क्षेत्र के किसान भारी परेशान हो रहे हैं। नामांतरणए बटवाराए नक्शा तरमीमए सीमांकन आदि कार्यो के लिए किसान कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं। जिसमें क्षेत्रीय किसान प्रमोद साहू पिंडरुखी ने बताया कि उसके द्वारा फरवरी माह में जमीन खसरा क्रमांक 565ध्2 रकवा 0ध्14 हेण क्रय की गई हैं। जिस भूमि का नामांतरण भी हो चुका हैं। परंतु नक्शा तरमीम ना होने से सीमांकन नहीं हो पा रहा हैं। अब बारिश लगनी वाली हैं और ऐसी स्थिति में कृषि कार्य भी नहीं हो सकेगा। इसके लिए किसान ने मार्च माह में आवेदन किया हुआ हैं। परंतु आज कल में टाल दिया जाता हैं। इस प्रकार अनेक किसान प्रतिदिन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जोकि किसानों के लिए वर्तमान समय में भारी परेशानी का कारण बनी हुई हैं।

बैगाचक में महकी जैविक आमों की खुशबूए बैगा किसान ने कलेक्टर को भेंट किए आम

डिंडौरी। जिले के बजाग विकासखंड अंतर्गत बैगा बाहुल्य बैगाचक क्षेत्र में जनजातीय किसानों की मेहनत अब फल देने लगी है। ग्राम पंचायत घोपतपुर के बंजरटोला निवासी प्रगतिशील बैगा किसान मोती सारीवान ने अपने बाग में तैयार जैविक एवं प्राकृतिक तरीके से उगाए गए उच्च गुणवत्ता वाले आम जिला कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया को भेंट किए।गौरतलब है कि नाबार्ड ;छाठ।त्वद्ध द्वारा प्रायोजित एवं एसआरपीडीआर भोपाल द्वारा संचालित वाडी परियोजना के तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के किसानों के बागों में आम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। इससे जनजातीय किसानों की आय बढ़ने की नई संभावनाएं विकसित हुई हैं। कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने आमों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए किसान मोती सारीवान के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वाडी परियोजना जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की

दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से किसानों को स्थायी आजीविका के अवसर मिल रहे हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।कलेक्टर ने परियोजना से जुड़े किसानों को मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन जैसी आयवर्धक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित विविध आजीविका गतिविधियों से किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सहकारी गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ;डीडीएमद्धए एसआरपीडीआर संस्था के परियोजना समन्वयक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वाडी परियोजना की सफलता से बैगाचक क्षेत्र के किसानों में उत्साह का माहौल है और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हो रही है।

गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का भक्तिमय आयोजन, उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़

डिंडौरी। नगर स्थित गायत्री मंदिर परिसर में इन दिनों श्रीमद्भागवत कथा का भव्य एवं भक्तिमय आयोजन चल रहा है। कथा के शुभारंभ से ही श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण हेतु पहुंच रहे हैं और धर्मए भक्ति तथा आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।कथा वाचक द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओंए भक्त प्रह्लादए ध्रुव चरित्र एवं भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का सरल एवं प्रेरणादायक वर्णन किया जा रहा है। कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को सत्यए सेवाए सदाचार एवं मानव कल्याण का संदेश दिया जा रहा है।कथा स्थल पर भजन.कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु कथा श्रवण के साथ.साथ सामूहिक आरती एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारा एवं पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

गाड़ासरई में लगा निशुल्क परामर्श शिविर

गाड़ासरई – सोमवार को गाड़ासरई स्थित संजीवनी क्लिनिक में निःशुल्क परामर्श शिविर लगाया गया जिसमे नागपुर होप हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर बी के मुरली आर्थोपेडिग व स्पाइन सर्जन के साथ बहुत से डॉक्टर उपस्थित हुए, और सभी डॉक्टर ने उपस्थित लोगों की हर प्रकार की बीमारी की बारीकी से जॉच कर उनको उपचार व उचित परामर्श दिया, और शिविर में सुबह से लेकर शाम तक इलाज कराने वालों की भीड़ देखने की मिली और शाम तक लगभग सौ से ज्यादा लोगो ने निःशुल्क शिविर का लाभ लिया जानकारी के

आभाव में बहुत से लोग इलाज कराने में चूक जाते है, या बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते है ,उन्ही लोगो के इलाज के उद्देश्य से शिविर आयोजित किया गया है,बीच बीच मे ऐसे बहुत से निःशुल्क शिविर गाड़ासरई के संजीवनी क्लिनिक में आयोजित किए जाते है जिसमे गम्भीर बीमारियों से बचाव होते है और उसका लाभ आसपास के लोगों को निशुल्क शिविर में मिल रहा है।

हरिभूमि

नर्मदा भूमि

[करेली | तेंदूखेड़ा | श्रीधाम | सालीचौका | सुआतला | गाडरवारा | राजमार्ग | साईंखेड़ा | चीचली | करकबेल]

जबलपुर, बुधवार 17 जून 2026

login : www.haribhoomi.com

कलेक्टर व एसपी ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

सड़क सुरक्षा के लिए दिए निर्देश

जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा स्पीड ब्रेकर निमार्ण रेड, चिन्ह आदि बनाना, मोड़ पर मिरर लगाना ऐसे अनेक कार्यो के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करना तथा निरंतर वाहन चालकों से समझाइस देकर समझना आदि कार्य निरंतर कार्य किया जा रहा है। पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुचाने के लिए लोगों को समझाना आदि कार्य को लेकर सजग रहने के लिए प्रेरित करना। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समीति की बैठक ली गई।

दिए आवश्यक दिशा निर्देश

मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को ली। आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया, मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अरविंद किटहा अरविंद किटहा, यातायात निरीक्षक श्रीमती ममता तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक में सड़क मार्गों में स्थित गड्ढों और साईड शोल्डरों का भराव किया जाए। उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले के सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में यातायात व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संचालित हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

यातायात नियमों को हो पालन

आयोजित बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने बैहर तिराहा पर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु प्रस्ताव और शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए सर्विस लाइन (ले-बाय) निर्माण के निर्देश दिए। जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे ब्लैक स्पॉट्स पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोका जा सके। गाडरवारा नगर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर, स्पीड लिमिट के सांकेतिक बोर्ड और सड़क के किनारे साइड सोल्डर बनाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर के विपतपुरा अंडरपास में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए हाईट बैरियर की ऊंचाई कम करने के निर्देश दिए गए, ताकि बड़े वाहन अंडरपास में प्रवेश न कर सकें और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।

ठोस कार्रवाई करने के निर्देश

बैठक के दौरान कलेक्टर एवं एसपी अधिकारियों से दुर्घटनाओं के कारण तथा रोड पर होने वाले गड्ढे तथा सोल्डर निर्माण करने की बात कही। पुलिस सड़क दुर्घटना को रोकने में प्रशासन का पूरा प्रयास करें तथा सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहे साथ ही यातयात नियमों को पूरी तरह से पालन किया जाए। किसी भी वाहन की संदिग्ध होने पर पुलिस को सूचना जरूर दी जाए। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान जिले मे होने वाली दुर्घटनाओं के स्पॉटों पर भी चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है।

खबर संक्षेप

मंत्री श्री पटेल आज नगर के मास्टर प्लान की बैठक लेंगे

नरसिंहपुर। प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में 17 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नरसिंहपुर नगर के मास्टर प्लान के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा है।

जनसुनवाई में आये 140 आवेदन

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आवेदकों ने विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 140 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हो सका, उन आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया।

विद्यालय भवनों की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाएः डीईओ

नरसिंहपुर। वर्षा काल के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं विद्यालयों के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा द्वारा जिले के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधान पाठकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि अतिवृष्टि के दौरान विद्यालय भवनों की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाए। यदि किसी विद्यालय भवन अथवा कक्ष की स्थिति जर्जर, क्षतिग्रस्त या असुरक्षित पाई जाती है तो ऐसे भवनों में कक्षाओं का संचालन नहीं कराया जाए। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के तहत विकासखंड स्तर पर समस्त शासकीय विद्यालयों का निरीक्षण कर भवनों की सुरक्षा स्थिति का परीक्षण कराया जाएगा। जिन भवनों अथवा कक्षों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जर्जर या खतरनाक घोषित किया गया है, उनमें कक्षाओं का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय भवनों में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही समय-समय पर निरीक्षण एवं निगरानी कर विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

संघठन की बैठक में शामिल हुए जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड

सौंसर। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, भोपाल में आयोजित महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में पांढुर्णा भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड ने सहभागिता की, भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026' के अंतर्गत आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के कौशल विकास पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रभारी श्री के. सी. पटेल ने कार्यकर्ताओं को ओजस्वी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा एवं जबलपुर संभाग की संयुक्त संगठनात्मक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रदेश नेतृत्व ने संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन किया। इस दौरान पांढुर्णा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड ने जिले की संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्ययोजनाओं का विस्तृत ब्योरा वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किया।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया बरमान का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने सोमवार को बरमान में आयोजित सोमवती अमावस्या के एक दिवसीय मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोमवती अमावस्या के अवसर पर जिले सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा जी में स्नान के लिए बरमान पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मेले में एसडीआरएफ के जवान, होमगार्ड तथा जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए मोटर बोट के माध्यम से निरंतर गश्त करने के निर्देश दिए। साथ ही माइक के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट कर श्रद्धालुओं को सतर्क रहने हेतु जागरूक किया जा रहा है। नाव संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त मेले क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा संबंधी संकेतक बोर्ड भी लगाए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित पंचायत को साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती कलावती ब्यारे सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

नगर पटवा -लखेरा समाज का गठन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

विगत दिवस अखिल भारतीय पटवा में समाज सभा के तहत नरसिंहपुर नगर पटवा समाज की आवश्यक बैठक प्रदेश सहप्रचार मंत्री डॉ. राजकुमार पटवा के निवास पर रखी गई जिसमें नगर पटवा समाज की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नगर अध्यक्ष राकेश पटवा एवं सचिव प्रशांत पाटकर व अन्य पदाधिकारी को चयन किया गया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में समस्त पटवा समाज के द्वारा पटवा समाज को विश्वकर्मा योजना के तहत पटवा समाज कल्याण बोर्ड के गठन हेतु मांग जोरों पर उठ रही है सभी प्रदेश पदाधिकारी ,जिला व नगर अध्यक्ष द्वारा स्थानीय विधायकों और मंत्रियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। बैठक में विभिन्न सुझावों पर चर्चा की है जिसमें समाज मे ऐसी प्रतिभाएं हैं जो समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं उनका सम्मान समारोह ,वरिष्ठ समाज बंधु जो लगातार विगत वर्षों से समाज में सक्रिय व समाज उत्थान में भूमिका निभा रहे हैं उनका अभिनंदन मंच द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी प्रदेश सह प्रचार मंत्री डॉ राजकुमार पटवा द्वारा प्रेषित की गई।

पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में पुलिस का शानदार प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

बीते दिनों जबलपुर में आयोजित 25 वीं पूर्वी जोन अंतर-जिला पुलिस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2026 में जिला नरसिंहपुर के पुलिस खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट एवं सराहनीय प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में टीम ने अनुशासन, समर्पण एवं खेल कौशल का परिचय देते हुए नरसिहंपुर पुलिस टीम द्वारा हैंडबॉल एवं फुटबॉल में प्रथम स्थान साथ ही बास्केटबॉल एवं हॉकी में द्वितीय स्थान प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। हैंडबॉल टीम में आरक्षक अमित रजक, प्रधान आरक्षक तनजीम रिज्वी, अजय पासी, विनय बर्थवाल, अभिषेक पासी, नसीम, आशीष एवं विशाल चैकसे, फुटबॉल टीम में उनि गौरव नेमा, प्रधान आरक्षक तनजीम रिज्वी, आरक्षक अजय पासी, यशराज, अभिषेक पासी, हरीश मुडिया, अभिषेक बस्तवार, वियन बर्थवाल, नदीम, प्रवीन, नसीम, शान्तनु, हॉकी टीम में प्रधान आरक्षक तनजीम रिज्वी, आरक्षक राघवेन्द, अभिषेक बस्तवार, अभिषेक पासी, अजय पासी, हरीश मुडिया, याशराज सिंह, दीपक कोल, पवन रजक, विनय, राहुल पाठक एवं नसीम, बास्केटबॉल टीम में प्रधान आरक्षक तनजीम रिज्वी, आरक्षक विनय बर्थवाल, नदीम, अजय पासी, आशीष सिलावट एवं पवन रजक तथा कुश्ती, वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित खिलाड़ियों पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

डीजल विक्रय पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

नरसिंहपुर। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश 2026 लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) द्वारा डीजल केवल वाहनों के टैंक में अथवा पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही विक्रय किया जाएगा। साथ ही एक दिन में एक ग्राहक / वाहन को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही प्रदान किया जा सकेगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि खरीदा गया डीजल पुनः बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता खुदरा विक्रय केन्द्रों से डीजल एवं पेट्रोल की खरीदी नहीं करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों के माध्यम से ही करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश के पालन हेतु जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं ऑयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

चौरई ब्लॉक किसान कांग्रेस ने किसान हित में सौंपा ज्ञापन

डीजल पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते प्रभावित कृषि कार्यों से अवगत कराया

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देशन पर वर्तमान समय में किसानों के समक्ष उत्पन्न हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक किसान कांग्रेस चौरई द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी चौरई को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों की प्रमुख समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की गई।

प्रस्तुत ज्ञापन में डीजल की आपूर्ति में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। केन एवं कुप्पियों में डीजल देने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण किसानों को समय पर डीजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती-किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे। उन्होंने इस व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर किसानों को सुगम एवं निर्बाध डीजल उपलब्ध कराने की मांग की। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुशील सक्सेना ने कहा कि क्षेत्र में खाद एवं उर्वरकों की उपलब्धता भी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद-उर्वरक उपलब्ध न होने से कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने शासन-प्रशासन से किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद एवं उर्वरकों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।

ज्ञापन के दौरान किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय किसानों की अन्य समस्याओं से भी अनुविभागीय अधिकारी को अवगत कराया तथा किसानों के हित में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो किसानों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संगठन ने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ किसानों की मांगों पर विचार कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा व्यक्त की।

तेंदूखेड़ा के मोहांश गोल्डन बुक आफ दा वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल

तेंदूखेड़ा। नगर के प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी संदीप कुमार जैन के छोटे भाई अभिषेक जैन के पुत्र मोहांश जैन जिनकी उम्र अभी मात्र साढ़े आठ वर्ष की है इतनी कम उम्र

में उनका नाम गोल्डन बुक आफ दा वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना तेंदूखेड़ा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है।मोहांश ने बहुत ही छोटी उम्र में जैन दर्शन के अति प्राचीन संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के पांच ग्रंथों को कंठस्थ याद किया है।लौकिक क्षेत्र की जगह अपने धर्म ग्रंथों से संबंधित रिकॉर्ड बनाना हम लोगों को और भी अधिक गर्व का विषय है।मोहांश ने जिन ग्रंथों को कंठस्थ याद किया है। उनमें श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारश्री तत्त्वार्थ सूत्र श्री द्रव्य संग्रह श्री इष्टोपदेश श्री भक्तामर स्तोत्र प्रमुख रुप से शामिल हैं। मोहांश की इस सफलता पर सभी वर्गों के लोगों ने को बधाइयां और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की है।

खतरों से खेलते कर्मवीरों को जरुरत है सुरक्षा उपकरणों की

तेंदूखेड़ा

आम आदमी के दैनिक जीवन में शामिल हो चुकी बिजली की व्यवस्था को लेकर 24 घंटे तत्पर रहने वाले विद्युत कर्मचारी जो सबको प्रकाश में रखना चाहते हैं।भीषण गर्मी हो या बरसात ठंड का मौसम विजली कर्मी शिकायत सूचना मिलने पर तत्काल हाजिर हो जाते हैं। लेकिन इनकी चिंता शायद किसी को भी नहीं है। बरसात के दिनों में नंगे हाथों पैरों से विद्युत पोलों पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं होता है। इन कर्मियों के पास ना तो हेंडग्लोब्ज हैं ना डिस्चार राड रेनकोट टार्च जूते प्लास्टर तक नहीं है बरसात के पूर्व इनकी सुरक्षा जरूरी है।यही कर्मचारी को विद्युत बसूली से लेकर सुधार कार्य में भी अपनी सहभागिता निभानी पड़ती है।